EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

03 Feb 2026

EXAM Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK | RAILWAY Exam

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !

Ques: What is the maximum timeline prescribed by RBI for banks to take credit decisions on loans up to ₹25 lakh for Micro and Small Enterprises?
माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए ₹25 लाख तक के ऋण पर क्रेडिट निर्णय लेने हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा क्या है?

A) 7 working days
B) 10 working days
C) 14 working days
D) 21 working days
E) 30 working days

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The investment and turnover limits for classification of MSMEs have been revised to enable higher efficiency of scale, technology upgradation, better access to capital, and global competitiveness.
• एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं में संशोधन किया गया है ताकि बड़े पैमाने की दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी तक बेहतर पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।
• As per RBI (informed by DFS), for loans up to ₹25 lakh to Micro and Small Enterprises, banks must take credit decisions within 14 working days.
• डीएफएस द्वारा सूचित आरबीआई के अनुसार, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को ₹25 लाख तक के ऋण के लिए बैंकों को 14 कार्यदिवसों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेना होगा।
• For loans above ₹25 lakh, timelines will follow board-approved sanction time norms of banks.
• ₹25 लाख से अधिक के ऋण के लिए समय-सीमा बैंकों के बोर्ड-अनुमोदित स्वीकृति मानकों के अनुसार होगी।
• Banks are required to prominently display MSME credit-related information, timelines, and indicative document checklists on their websites.
• बैंकों को एमएसएमई से जुड़े क्रेडिट विवरण, समय-सीमा और दस्तावेज़ सूची अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
• Under CGTMSE, loan applications, sanctions, and disbursements under the Credit Guarantee Scheme (CGS) for MSEs are monitored quarterly by the Empowered

Committee on MSME chaired by RBI along with SLBCs.

• सीजीटीएमएसई के तहत, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGS) में ऋण आवेदन, स्वीकृति और वितरण की तिमाही निगरानी आरबीआई अध्यक्षता वाली एमएसएमई सशक्त समिति और एसएलबीसी द्वारा की जाती है।

• The credit guarantee cover for MSEs has been enhanced from ₹5 crore to ₹10 crore with effect from 01.04.2025 under CGS.

• सीजीएस के तहत एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 01.04.2025 से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।

Recent News Headlines Related to RBI

• The RBI has proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and the associated capital requirements.
• आरबीआई ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और उससे जुड़ी पूंजी आवश्यकताओं की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

• The Reserve Bank of India (RBI) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and information exchange related to Central Counterparties (CCPs).
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण (ESMA) ने सेंट्रल काउंटरपार्टी (CCPs) से जुड़े सहयोग और सूचना आदान-प्रदान के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए।

• The Reserve Bank of India released the report titled "State Finances: A Study of Budgets of 2025–26".
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने "स्टेट फाइनेंसेज़: बजट्स का अध्ययन 2025–26" नामक रिपोर्ट जारी की।

• RBI granted in-principle approval to Payoneer India Private Limited, a subsidiary of US-based Payoneer Global, to operate as a PA–Cross Border.
• RBI के अनुसार, पेयोनीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Payoneer Global की सहायक कंपनी) को PA–क्रॉस बॉर्डर के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

• Reserve Bank of India (RBI) granted in-principle approval to Payoneer India Private Limited, a subsidiary of United States of America (USA)- based Payoneer Global, to operate as a Payment Aggregator – Cross Border (PA-CB)
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अमेरिका स्थित Payoneer Global की सहायक कंपनी Payoneer India Private Limited को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर (PA-CB) के रूप में संचालन करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

• Razorpay's offline payments arm, Razorpay POS (Point of Sale), has received the Payment Aggregator – Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI)
• Razorpay की ऑफलाइन भुगतान शाखा, Razorpay POS (प्वाइंट ऑफ सेल), को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से भौतिक भुगतान एग्रीगेटर (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हो गया है।

Ques: Which bank has received RBI approval to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gujarat?
किस बैंक को गुजरात के GIFT सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में शाखा खोलने के लिए RBI की मंज़ूरी मिली है?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
D) Canara Bank / केनरा बैंक
E) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Punjab & Sind Bank has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.
• पंजाब एंड सिंध बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी के IFSC में शाखा खोलने की अनुमति मिली है।
• GIFT City IFSC is India's premier international financial hub, created to facilitate cross-border financial transactions.
• GIFT सिटी IFSC भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, जिसे सीमा-पार वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।
• It provides a world-class ecosystem for international trade finance, offshore banking, and capital market activities.
• यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, ऑफशोर बैंकिंग और पूंजी बाज़ार गतिविधियों के लिए विश्वस्तरीय ढांचा उपलब्ध कराता है।

About Punjab & Sind Bank :

• Established : 1908
• HQ : New Delhi
• MD & CEO : Swarup Kumar Saha
• Tagline : Where service is a way of life

Ques: As per the revised World Bank International Poverty Line, what was India's extreme poverty rate in 2022–23?
संशोधित विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार 2022–23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी?

A) 3.1%
B) 4.5%
C) 5.3%
D) 12.9
E) 23.9%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The World Bank has revised the International Poverty Line (IPL) from USD 2.15 to USD 3.00 per day, adjusted for 2021 Purchasing Power Parity (PPP).
• विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को USD 2.15 प्रति दिन से बढ़ाकर USD 3.00 प्रति दिन कर दिया है, जो 2021 की क्रय शक्ति समता (PPP) के अनुसार समायोजित है।
• The revision accounts for changes in global price levels and consumption patterns.
• यह संशोधन वैश्विक मूल्य स्तर और उपभोग पैटर्न में आए बदलावों को दर्शाता है।
• According to the revised IPL, India's extreme poverty rate in 2022–23 stood at 5.3%.
• संशोधित IPL के अनुसार, वर्ष 2022–23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 5.3% रही।
• India's lower-middle-income poverty rate in 2022–23 was estimated at 23.9%.
• 2022–23 में भारत की निम्न-मध्यम आय वर्ग गरीबी दर 23.9% आंकी गई।
• These estimates are highlighted in the Economic Survey.
• ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं।

Recent News Headlines Related to Awards & Winners :

- Wiley Research Heroes Prize 2025 : Dr. Chandrakant Lahariya
- विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025: डॉ. चंद्रकांत लहरिया

- President's Police Colour Award (Nishaan) : Sikkim Police
- राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार (निशान): सिक्किम पुलिस

- Padmapani Award : Renowned music maestro Ilaiyaraaja
- पद्मपाणि पुरस्कार: प्रसिद्ध संगीत उस्ताद इलैयाराजा

- SKOCH Award-2025 : Centre for Development of Telematics (C-DOT) for its Cell Broadcast Solution (CBS)
- स्कोच पुरस्कार-2025: टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन (सीबीएस) के लिए।

- Gold Medal of the Royal Astronomical Society (RAS) : US-based Indian-origin astronomer Professor Shrinivas Kulkarni
- रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी (आरएएस) का स्वर्ण पदक: अमेरिका स्थित भारतीय मूल के खगोलशास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी

- Ati Vishisht Rail Seva Puraskar : Chandana Sinha, an officer of the Railway Protection Force (RPF)
- अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार: चंदना सिन्हा, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की अधिकारी

- 'Best Fintech & DPI Adoption' award : Karnataka Bank
- 'बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन' पुरस्कार: कर्नाटक बैंक

- The Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2025 : Graca Machel, a Mozambican rights activist
- इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025: मोज़ाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल

- Tyler Prize for Environmental Achievement : American evolutionary biologist Toby Kiers
- पर्यावरण क्षेत्र में उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार: अमेरिकी विकासवादी जीवविज्ञानी टोबी कियर्स

- Samurai martial arts honour : Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan

Ques: In which locations will the pilot project of CBDC-based "digital food currency" under the free ration scheme be rolled out?
मुफ़्त राशन योजना के तहत CBDC आधारित "डिजिटल फूड करेंसी" की पायलट परियोजना किन स्थानों पर शुरू की जाएगी?

A) Chandigarh, Puducherry and three districts of Gujarat / चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिले
B) Delhi, Mumbai and Chennai / दिल्ली, मुंबई और चेन्नई
C) Gujarat and Rajasthan only / केवल गुजरात और राजस्थान
D) All Union Territories of India / भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश
E) Punjab, Haryana and Himachal Pradesh / पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India is set to roll out a pilot project for Central Bank Digital Currency (CBDC), also called "digital food currency", under the free ration scheme.
• भारत सरकार मुफ़्त राशन योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) यानी "डिजिटल फूड करेंसी" का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
• The pilot will be implemented in Chandigarh, Puducherry, and three districts of Gujarat.
• यह पायलट चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिलों में लागू किया जाएगा।
• Beneficiaries will receive monthly digital food coupons directly into an RBI-enabled digital wallet on their mobile phones.
• लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर RBI-सक्षम डिजिटल वॉलेट में मासिक डिजिटल फूड कूपन मिलेंगे।
• Coupons can be redeemed at ration shops by scanning the QR code of the shop owner to obtain free foodgrains.
• राशन दुकानदार के QR कोड को स्कैन कर कूपन भुनाए जा सकेंगे और निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा।
• A soft launch was conducted earlier in Ahmedabad with 25 beneficiaries.
• इससे पहले अहमदाबाद में 25 लाभार्थियों के साथ इसका सॉफ्ट लॉन्च किया गया था।
• The next phase will cover Anand, Sabarmati and Dahod districts of Gujarat.
• अगले चरण में गुजरात के आणंद, साबरमती और दाहोद जिलों को शामिल किया जाएगा।

Ques: Who has issued draft guidelines on resolution plans for borrowers affected by natural disasters?
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाओं पर मसौदा दिशानिर्देश किसने जारी किए हैं?

A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
B) National Disaster Management Authority / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
C) State Governments / राज्य सरकारें
D) NITI Aayog / नीति आयोग
E) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has issued draft guidelines for banks and other regulated entities on resolution plans during natural disasters.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समाधान योजनाओं को लेकर बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• The framework will be applicable from April 1, and RBI has invited public and stakeholder feedback until February 17.
• यह ढांचा 1 अप्रैल से लागू होगा और RBI ने 17 फरवरी तक सार्वजनिक एवं हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
• The proposed framework requires banks to proactively plan for natural calamities while framing their credit policies, instead of relying on ad hoc relief measures.
• प्रस्तावित ढांचे के तहत बैंकों को तदर्थ राहत उपायों के बजाय क्रेडिट नीतियाँ बनाते समय प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजना बनानी होगी।
• Banks will need to assess climate risks in advance and prepare pre-defined resolution mechanisms.
• बैंकों को जलवायु जोखिमों का पूर्व मूल्यांकन कर पूर्व-निर्धारित समाधान तंत्र तैयार करना होगा।
• RBI has clarified that only standard borrowers will be eligible for relief.
• RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल मानक (स्टैंडर्ड) उधारकर्ता ही राहत के पात्र होंगे।
• Borrowers who have not defaulted for more than 30 days at the time of the disaster will qualify for relief.
• आपदा के समय जिन उधारकर्ताओं ने 30 दिनों से अधिक की चूक नहीं की है, वे राहत के लिए पात्र होंगे।

Ques: At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at what percentage of the FY26 Budget Estimate?
दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा FY26 के बजट अनुमान का कितना प्रतिशत था?

A) 48.0%
B) 50.2%
C) 52.8%
D) 54.5%
E) 56.7%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at ₹8.55 lakh crore, which was 54.5% of the FY26 Budget Estimate.
• दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा ₹8.55 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के बजट अनुमान का 54.5% था।
• This level was lower than the 56.7% of the annual target recorded during the same period in the previous year.
• यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 56.7% के स्तर से कम था।
• The improvement in fiscal position was driven by stronger tax revenues and a fiscal surplus recorded in December.
• राजकोषीय स्थिति में यह सुधार मजबूत कर राजस्व और दिसंबर में दर्ज राजकोषीय अधिशेष के कारण हुआ।
• Gross tax revenues rose sharply by 32.3% in December, taking overall growth during April–December to 8.5%.
• दिसंबर में सकल कर राजस्व 32.3% बढ़ा, जिससे अप्रैल–दिसंबर अवधि की कुल वृद्धि 8.5% हो गई।
• Capital expenditure growth slowed during this period, which helped in containing the fiscal deficit.
• इस अवधि में पूंजीगत व्यय की वृद्धि धीमी रही, जिससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिली।
• The government has targeted limiting the full-year FY26 fiscal deficit to 4.4% of GDP.
• सरकार ने पूरे FY26 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।

Ques: Who is set to become the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra?
महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री कौन बनने जा रही हैं?

A) Supriya Sule / सुप्रिया सुले
B) Sunetra Pawar / सुनेत्रा पवार
C) Pankaja Munde / पंकजा मुंडे
D) Rohini Khadse / रोहिणी खडसे
E) Amruta Fadnavis / अमृता फडणवीस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Sunetra Pawar is set to become the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra, creating history in the state's political landscape.
• सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, जिससे राज्य की राजनीति में इतिहास रचेगा।
• She is the wife of senior Nationalist Congress Party (NCP) leader Ajit Pawar.
• वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित पवार की पत्नी हैं।
• The decision was taken unanimously by the NCP leadership.
• यह निर्णय NCP नेतृत्व द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
• The Maharashtra government has assured its support to the NCP's decision.
• महाराष्ट्र सरकार ने NCP के इस निर्णय को समर्थन देने का आश्वासन दिया है।
• With this appointment, Sunetra Pawar will become the first woman to hold the post of Deputy Chief Minister in Maharashtra.
• इस नियुक्ति के साथ सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला बन जाएंगी।

Ques: As on January 24, 2026, what percentage of rural households have tap water supply under Jal Jeevan Mission?
24 जनवरी 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध है?

A) 65%
B) 72%
C) 75%
D) 81.56%
E) 90%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Jal Jeevan Mission (JJM) has been implemented since August 2019 by the Government of India in partnership with States to provide potable tap water to every rural household.
• जल जीवन मिशन (JJM) अगस्त 2019 से भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है।
• The total estimated outlay of the Mission is ₹3.60 लाख करोड़, of which the Central share is ₹2.08 लाख करोड़.
• मिशन का कुल अनुमानित परिव्यय ₹3.60 लाख करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹2.08 लाख करोड़ है।
• At the launch of the Mission, only 3.23 करोड़ (17%) rural households had tap water connections.
• मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन था।
• As reported by States and Union Territories, about 12.56 करोड़ additional rural households were provided tap water connections till 24.01.2026.
• राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार, 24.01.2026 तक लगभग 12.56 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल से जल कनेक्शन दिया गया है।
• As on 24.01.2026, out of 19.36 करोड़ rural households, more than 15.79 करोड़ households have tap water supply at home, which is 81.56% coverage.
• 24.01.2026 तक कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.79 करोड़ से अधिक घरों (81.56%) में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध है।
• Water is a State subject, and the implementation as well as saturation plans are carried out by the respective States and Union Territories.
• जल एक राज्य विषय है, तथा इसका कार्यान्वयन और संतृप्ति योजना संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की जाती है।

Ques: Which cricketer has been provisionally banned by the International Cricket Council (ICC) under its Anti-Corruption Code?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत किस क्रिकेटर को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया है?

A) Shai Hope / शाई होप
B) Nicholas Pooran / निकोलस पूरन
C) David Warner / डेविड वॉर्नर
D) Aaron Jones / एरॉन जोन्स
E) Jason Holder / जेसन होल्डर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The International Cricket Council (ICC) has provisionally banned USA batter Aaron Jones from all formats of cricket under its Anti-Corruption Code.
• अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अमेरिका के बल्लेबाज़ एरॉन जोन्स को भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत सभी प्रारूपों से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
• Aaron Jones faces five charges related to alleged breaches of anti-corruption rules under both the ICC and Cricket West Indies (CWI) codes.
• एरॉन जोन्स पर ICC और क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) की भ्रष्टाचार रोधी संहिताओं के तहत पाँच आरोप लगाए गए हैं।
• He has been given 14 days from 28 January 2026 to submit a formal response to the charges.
• उन्हें आरोपों पर औपचारिक जवाब देने के लिए 28 जनवरी 2026 से 14 दिन का समय दिया गया है।
• Due to the suspension, he is ineligible for selection in the 2026 ICC Men's T20 World Cup, which begins on 7 February 2026.
• इस प्रतिबंध के कारण वह 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए चयन के अयोग्य हो गए हैं।

Ques: Which PSU secured the 'Great Place to Work' certification for the third consecutive year (2026–27)?
किस PSU को 2026–27 के लिए लगातार तीसरी बार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन प्राप्त हुआ है?

A) BHEL / भेल
B) ONGC / ओएनजीसी
C) GAIL / गेल
D) NTPC / एनटीपीसी
E) Steel Authority of India Limited (SAIL) / स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Steel Authority of India Limited (SAIL) has secured the 'Great Place to Work' certification for the period February 2026 to February 2027 for the third consecutive year.
• स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए लगातार तीसरी बार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
• SAIL is a Maharatna Public Sector Undertaking (PSU) and India's largest public sector steel manufacturer under the Ministry of Steel.
• SAIL एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी है।
• The certification was awarded after a company-wide assessment conducted by the Great Place to Work Institute, India.
• यह प्रमाणन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा किए गए कंपनी-स्तरीय मूल्यांकन के बाद प्रदान किया गया।
• SAIL recorded a significant improvement in its TRUST INDEX© score, reflecting strong workplace culture and positive employee feedback.
• SAIL के TRUST INDEX© स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो मजबूत कार्यस्थल संस्कृति और कर्मचारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
• The recognition highlights SAIL's focus on transparent, performance-driven HR practices and employee initiatives such as 'SAIL DARPAN'.
• यह सम्मान पारदर्शी, प्रदर्शन-आधारित HR प्रथाओं और 'SAIL DARPAN' जैसे कर्मचारी विकास कार्यक्रमों के प्रति SAIL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Ques: How many tableaux participated in the 77th Republic Day Parade 2026 on Kartavya Path?
77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियाँ (टैब्लो) प्रदर्शित की गईं?

A) 25 tableaux
B) 27 tableaux
C) 28 tableaux
D) 30 tableaux
E) 32 tableaux

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• A total of 30 tableaux rolled down Kartavya Path during the 77th Republic Day Parade 2026.
• 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियाँ प्रदर्शित की गईं।
• These included 17 tableaux from States and Union Territories and 13 tableaux from Ministries, Departments and Services
• इनमें शामिल थीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियाँ और मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की 13 झांकियाँ
• The overall theme of the Republic Day tableaux revolved around two core ideas "Svatantrata Ka Mantra – Vande Mataram" and "Samriddhi Ka Mantra – Aatmanirbhar Bharat"
• गणतंत्र दिवस झांकियों की मुख्य थीम थीं "स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्" और "समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत"
• The winners of the tableaux are selected by an expert jury constituted by the Ministry of Defence.
• झांकियों के विजेताओं का चयन रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ जूरी द्वारा किया जाता है।
• Additionally, a Popular Choice Award is given based on public voting through platforms like MyGov and SMS-based systems.
• इसके अतिरिक्त, MyGov और SMS आधारित मतदान के माध्यम से पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी दिया जाता है।
• States not selected for the main parade can showcase their tableaux at Bharat Parv, held at the Red Fort from January 26 to 31.
• मुख्य परेड में चयन न होने वाले राज्य 26–31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में अपनी झांकियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं।

Official Awards (Judges' Panel) :

• Best Marching Contingent (Services) (1st) - Indian Navy
• Best Marching Contingent (CAPF / Auxiliary Forces) (1st) - Delhi Police
• Best Tableau (States/UTs) (1st) - Maharashtra (Ganeshotsav: A Symbol of Aatmanirbharta)
• Best Tableau (States/UTs) (2nd) - Jammu & Kashmir (Handicrafts and Folk Dances of J&K)
• Best Tableau (States/UTs) (3rd) - Kerala (Water Metro & 100% Digital Literacy)
• Best Tableau (Central Ministries) - Ministry of Culture (Vande Mataram – The Soul Cry of a Nation)
• Special Prize - Central Public Works Department (CPWD) (Vande Mataram – Commemoration of 150 Years)
• Best Cultural Performance - Vande Mataram: The Eternal Resonance of India (Dance Presentation)

Popular Choice Awards (MyGov Public Voting) :

• Best Marching Contingent (Services) (1st) - Assam Regiment
• Best Marching Contingent (CAPF / Auxiliary Forces) (1st) - CRPF
• Best Tableau (States/UTs) (1st) - Gujarat (4th Consecutive Year) (Mantra of Swadeshi – Self-Reliance – Freedom)
• Best Tableau (States/UTs) (2nd) - Uttar Pradesh (Culture of Bundelkhand)
• Best Tableau (States/UTs) (3rd) - Rajasthan (Golden Touch of the Desert: Bikaner Gold Art) (Usta Art)
• Best Tableau (Central Ministries) - Dept. of School Education & Literacy (National Education Policy 2020)

RECENT LOANS AND AGREEMENTS :

• The World Bank has approved a loan of ₹5,700 crore for the Jal Sanrakshit Haryana Project.
• विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए ₹5,700 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।

• IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited (IGGEFIL) has sanctioned a USD 22.5 million loan to Swarna Solar Limited.
• इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड (IGGEFIL) ने स्वर्णा सोलर लिमिटेड को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।

• The World Bank approved a loan of USD 286 million for the West Bengal Health System Reform Program (WBHSRP).
• विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम (WBHSRP) के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया।

• Piramal Finance Limited has received a total loan of USD 350 million.
• पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है।

• Asian Development Bank provided ₹4,100 crore (USD 500 million) to the Government of Telangana.
• एशियाई विकास बैंक ने तेलंगाना सरकार को ₹4,100 करोड़ (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्रदान किए।

• The International Finance Corporation (IFC) has provided a loan of ₹300 crore (about USD 30 million) to the Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) issued by Grihum Housing Finance Limited.
• अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने गृहुम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी रेज़िडेंशियल मॉर्गेज-बैक्ड सिक्योरिटीज़ (RMBS) को ₹300 करोड़ (लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का ऋण प्रदान किया है।

• The World Bank has provided a loan of ₹9,821 crore to the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL).
• विश्व बैंक ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) को ₹9,821 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।

Ques: Which of the following personalities will be honoured with the Uttar Pradesh Gaurav Samman 2026 during Uttar Pradesh Day 2026?
निम्नलिखित में से किन व्यक्तित्वों को उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा?

A) Wing Commander Shubhanshu Shukla / विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला
B) Alakh Pandey / आलख पांडे
C) Dr Hariom Panwar / डॉ. हरिओम पंवार
D) Rashmi Arya / रश्मि आर्य
E) All of the above / उपरोक्त सभी

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Uttar Pradesh Government will honour five distinguished personalities with the Uttar Pradesh Gaurav Samman during Uttar Pradesh Day 2026.
• उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर पाँच विशिष्ट व्यक्तित्वों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी।
• The award recognises outstanding contributions in diverse fields and highlights the achievements of individuals who have brought pride to Uttar Pradesh.
• यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है।

• Awardees – Uttar Pradesh Gaurav Samman 2026:
– Wing Commander Shubhanshu Shukla – Space Science
– Alakh Pandey – Education
– Dr Hariom Panwar – Literature & Education
– Rashmi Arya – Women Empowerment
– Dr Sudhanshu Singh – Agriculture

• पुरस्कार विजेता – उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026:
– विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला – अंतरिक्ष विज्ञान
– आलख पांडे – शिक्षा
– डॉ. हरिओम पंवार – साहित्य एवं शिक्षा
– रश्मि आर्य – महिला सशक्तिकरण

Ques: The recently completed 100 m long 'Make in India' steel bridge is associated with which project?
हाल ही में पूरा किया गया 100 मीटर लंबा 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज किस परियोजना से संबंधित है?

A) Delhi–Meerut RRTS / दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस
B) Mumbai–Nagpur Samruddhi Expressway / मुंबई–नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे
C) Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project / मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना
D) Ahmedabad Metro Phase-II / अहमदाबाद मेट्रो चरण-II
E) Dedicated Freight Corridor / डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• A 100-metre-long 'Make in India' steel bridge has been successfully completed in Ahmedabad district for the Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project.
• मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अहमदाबाद जिले में 100 मीटर लंबा 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
• This is the 13th steel bridge completed in Gujarat out of a total of 17 steel bridges planned in the state.
• यह गुजरात में नियोजित कुल 17 स्टील ब्रिजों में से पूरा किया गया 13वां स्टील ब्रिज है।
• The bridge has been constructed over an underground metro tunnel connecting Kalupur and Shahpur metro stations.
• यह ब्रिज कालूपुर और शाहपुर मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने वाली भूमिगत मेट्रो सुरंग के ऊपर बनाया गया है।
• To avoid load transfer to the metro tunnel, the span length was increased to about 100 metres and the structure was redesigned as a Steel Truss Bridge.
• मेट्रो सुरंग पर भार न पड़े, इसके लिए स्पैन लंबाई लगभग 100 मीटर की गई और संरचना को स्टील ट्रस ब्रिज के रूप में पुनः डिज़ाइन किया गया।
• The bridge was assembled at a height of 16.5 metres on temporary trestles and later placed on permanent supports.
• ब्रिज को 16.5 मीटर की ऊँचाई पर अस्थायी ट्रेस्टल्स पर जोड़ा गया और बाद में स्थायी सपोर्ट पर स्थापित किया गया।
• The project strengthens high-speed rail connectivity while ensuring the safety of existing urban transport infrastructure.
• यह परियोजना हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करती है और मौजूदा शहरी परिवहन ढांचे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

India's Rankings in Different Indices

• Asia Manufacturing Index (AMI) 2026 : India (6th), China (1st)
• एशिया विनिर्माण सूचकांक (एएमआई) 2026: भारत (छठा स्थान), चीन (पहला स्थान)

• The Numbeo Safety Index 2026 was published by Numbeo : India (70th), UAE (1st)
• Numbeo द्वारा Numbeo सुरक्षा सूचकांक 2026 प्रकाशित किया गया: भारत (70वां स्थान), यूएई (पहला स्थान)

• Responsible Nations Index (RNI) : India (16th) , Singapore (1st)
• जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (आरएनआई): भारत (16वां स्थान), सिंगापुर (पहला स्थान)

• Export Preparedness Index 2024 published by NITI Aayog : Maharashtra (1st in Large States), Uttarakhand (1st in Small States)
• नीति आयोग द्वारा प्रकाशित निर्यात तैयारी सूचकांक 2024: महाराष्ट्र (बड़े राज्यों में प्रथम स्थान), उत्तराखंड (छोटे राज्यों में प्रथम स्थान)

• Henley Passport Index 2026 : India (80th), Singapore (1st)
• हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत (80वां), सिंगापुर (पहला)

• “Top Cities for Women in India 2025” report was published by Chennai-based workplace inclusion firm Avtar : Bengaluru (1st)
• चेन्नई स्थित कार्यस्थल समावेशन फर्म अवतार द्वारा प्रकाशित "भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2025" रिपोर्ट में : बेंगलुरु (पहला स्थान)

• The Global Food City Rankings 2025–26 were published by TasteAtlas : Mumbai (5th), Naples (1st)
• टेस्टएटलस द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 : मुंबई (5वां स्थान), नेपल्स (पहला स्थान)

• Bloomberg published the World’s Richest Families 2025 report : The Ambani Family (8th), Walton (1st)
• ब्लूमबर्ग द्वारा वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज़ 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की गई : अंबानी परिवार (आठवां), वाल्टन (पहला)

• 2025 Passport Index published by Arton Capital : India (67th) United Arab Emirates(UAE) (1st)
• आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2025 पासपोर्ट सूचकांक: भारत (67वां स्थान) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (पहला स्थान)

Ques: Which organisation has been formally designated as a terrorist organisation by the European Union, marking a major escalation in its policy towards Iran?
यूरोपीय संघ ने ईरान के प्रति अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए किस संगठन को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया है?

A) Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) / इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)
B) Hamas / हमास
C) Hezbollah / हिज़्बुल्लाह
D) Al-Qaeda / अल-कायदा
E) Houthis / हूती

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The European Union (EU) has formally designated Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a terrorist organisation.
• यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
• This decision marks a sharp escalation in EU policy towards Tehran.
• यह फैसला तेहरान के प्रति EU की नीति में बड़ा कड़ा कदम माना जा रहा है।
• The IRGC was established after the 1979 Islamic Revolution to safeguard Iran's clerical (theocratic) system.
• IRGC की स्थापना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की धार्मिक शासन प्रणाली की रक्षा के लिए की गई थी।
• Under EU law, the IRGC is now placed in the same legal terrorism category as al-Qaeda and ISIS, despite being a state-linked military force, unlike non-state militant groups.
• EU क़ानून के तहत IRGC को अब अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि IRGC एक राज्य से जुड़ी सैन्य शक्ति है।

Ques: Coking Coal has been notified as a Critical and Strategic Mineral under which Act?
कोकिंग कोल को किस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया गया है?

A) Coal Mines Act, 1973 / कोयला खान अधिनियम, 1973
B) MMDR Act, 1957 / MMDR अधिनियम, 1957
C) Environment Protection Act, 1986 / पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
D) National Steel Policy, 2017 / राष्ट्रीय स्टील नीति, 2017
E) Mines Act, 1952 / खान अधिनियम, 1952

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has notified Coking Coal as a Critical and Strategic Mineral under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
• भारत सरकार ने कोकिंग कोल को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया है।
• This decision supports the vision of Aatmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 by strengthening domestic mineral security.
• यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समर्थन देता है।
• The move is based on recommendations of the High-Level Committee on Viksit Bharat goals and policy inputs from NITI Aayog.
• यह कदम विकसित भारत लक्ष्यों पर उच्च-स्तरीय समिति और नीति आयोग के सुझावों के आधार पर लिया गया है।
• India has around 37.37 billion tonnes of coking coal resources, mainly concentrated in Jharkhand, with reserves also in Madhya Pradesh, West Bengal, and Chhattisgarh.
• भारत में लगभग 37.37 बिलियन टन कोकिंग कोल संसाधन हैं, जिनका प्रमुख हिस्सा झारखंड में तथा अन्य भंडार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हैं।
• Despite domestic availability, nearly 95% of the steel sector's coking coal requirement is met through imports.
• घरेलू उपलब्धता के बावजूद, स्टील क्षेत्र की लगभग 95% कोकिंग कोल आवश्यकता आयात से पूरी होती है।
• Declaring coking coal as a critical mineral will enable faster approvals, promote ease of doing business, accelerate exploration and mining, and reduce import dependence while supporting the National Steel Policy.
• कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिज घोषित करने से तेज़ मंज़ूरी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, खोज एवं खनन में तेजी आएगी, आयात निर्भरता घटेगी और राष्ट्रीय स्टील नीति को समर्थन मिलेगा।

Ques: The PM SVANidhi Credit Card launched by the Prime Minister aims to provide formal credit access to which group?
प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड किस वर्ग को औपचारिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए है?

A) Small farmers / छोटे किसान
B) Self-help group members / स्वयं सहायता समूह सदस्य
C) Street vendors / रेहड़ी-पटरी विक्रेता
D) MSME owners / एमएसएमई उद्यमी
E) Gig workers / गिग वर्कर्स

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Prime Minister of India launched the PM SVANidhi Credit Card to provide easy and formal credit access to street vendors.
• भारत के प्रधानमंत्री ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसान एवं औपचारिक ऋण सुविधा देने के लिए PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
• Eligibility: The credit card is available to street vendors who have successfully repaid the second tranche loan and are eligible for the third tranche under the PM SVANidhi Scheme.
• पात्रता: यह कार्ड उन रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए है जिन्होंने दूसरी किश्त का ऋण चुका दिया है और तीसरी किश्त के लिए पात्र हैं।

• Credit Features:
– Type: RuPay retail (personal) credit card
– Credit Limit: ₹30,000
– Facility: Revolving credit (amount can be reused after repayment)

• क्रेडिट की विशेषताएँ:
– प्रकार: रूपे रिटेल (पर्सनल) क्रेडिट कार्ड
– क्रेडिट सीमा: ₹30,000
– सुविधा: रिवॉल्विंग क्रेडिट (चुकाने के बाद पुनः उपयोग संभव)

• Objectives: Promote financial inclusion, reduce dependence on informal moneylenders, encourage digital transactions and credit discipline, and support small livelihoods.
• उद्देश्य: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम करना, डिजिटल लेन-देन और क्रेडिट अनुशासन को प्रोत्साहित करना तथा छोटी आजीविकाओं को समर्थन देना।

About PM SVANidhi Scheme | PM SVANidhi योजना के बारे में:

• PM SVANidhi stands for Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi.
• PM SVANidhi का पूर्ण रूप है — Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi।
• It was launched in 2020 as a Central Sector Scheme to provide affordable working capital loans to street vendors affected by the COVID-19 lockdown.
• इसे 2020 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य COVID-19 लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
• The scheme is implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and the Department of Financial Services (DFS).
• इस योजना का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा किया जाता है।

Ques: INOXGFL Group signed MoUs worth ₹17,000 crore to invest in the renewable energy sector with which state governments?
INOXGFL Group ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ₹17,000 करोड़ के निवेश हेतु किन राज्य सरकारों के साथ समझौते (MoUs) पर हस्ताक्षर किए?

A) Maharashtra, Gujarat and Rajasthan / महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान
B) Uttar Pradesh, Assam and Kerala / उत्तर प्रदेश, असम और केरल
C) Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh / तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
D) Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh / राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
E) Odisha, West Bengal and Bihar / ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• INOXGFL Group signed three Memoranda of Understanding (MoUs) worth ₹17,000 crore to invest in the renewable energy sector.
• INOXGFL Group ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ₹17,000 करोड़ के निवेश हेतु तीन समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
• The MoUs were signed with the governments of Uttar Pradesh, Assam and Kerala.
• ये समझौते उत्तर प्रदेश, असम और केरल की राज्य सरकारों के साथ किए गए।
• The agreements were signed at the World Economic Forum (WEF) Summit held in Davos, Switzerland.
• इन समझौतों पर दावोस, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

• **State-wise Investment Details:**
– Uttar Pradesh: ₹10,500 crore (initial agreement)
– Assam & Kerala: Combined investment of ₹6,500 crore

• राज्यवार निवेश विवरण:
– उत्तर प्रदेश: ₹10,500 करोड़ (प्रारंभिक समझौता)
– असम और केरल: संयुक्त रूप से ₹6,500 करोड़

Ques: What is India's Global Innovation Index (GII) rank in 2025?
2025 में भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रैंक क्या है?

A) 66th
B) 55th
C) 45th
D) 38th
E) 30th

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's Global Innovation Index (GII) rank improved to 38th in 2025 from 66th in 2019, indicating steady strengthening of the country's innovation performance.
• भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रैंक 2019 में 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है, जो देश की नवाचार क्षमता में निरंतर सुधार को दर्शाती है।
• This improvement reflects progress in innovation ecosystems, research, and technological capabilities.
• यह सुधार नवाचार इकोसिस्टम, अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं में प्रगति को दर्शाता है।
• The India Semiconductor Mission has approved 10 semiconductor manufacturing and packaging projects across 6 States.
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर निर्माण एवं पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
• These projects involve an investment of about ₹1.60 lakh crore.
• इन परियोजनाओं में लगभग ₹1.60 लाख करोड़ का निवेश शामिल है।
• The approved projects aim to strengthen India's domestic semiconductor manufacturing and packaging capabilities.
• स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण एवं पैकेजिंग क्षमता को मजबूत करना है।
• Together, the rise in GII ranking and progress under the Semiconductor Mission highlight India's growing focus on innovation-driven and technology-led development.
• GII रैंक में सुधार और सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति मिलकर नवाचार आधारित एवं प्रौद्योगिकी-प्रेरित विकास पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाते हैं।

Ques: Why did the Bombay Natural History Society (BNHS) sign a five-year MoU with the Chief Wildlife Warden of Jharkhand?
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने झारखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के साथ पाँच वर्षीय समझौता (MoU) क्यों किया?

A) To promote eco-tourism in Jharkhand / झारखंड में इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए
B) To conserve critically endangered vulture species / गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए
C) To establish new wildlife sanctuaries / नए वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना के लिए
D) To conduct a nationwide bird census / राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी जनगणना कराने के लिए
E) To promote commercial bird breeding / व्यावसायिक पक्षी प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Bombay Natural History Society (BNHS) has signed a five-year Memorandum of Understanding with the Chief Wildlife Warden of Jharkhand.
• बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने झारखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के साथ पाँच वर्ष का समझौता ज्ञापन (MoU) किया है।
• The objective of the MoU is to strengthen the conservation of critically endangered vulture species in the state.
• इस MoU का उद्देश्य राज्य में गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण को सुदृढ़ करना है।
• The agreement focuses on scientific breeding, monitoring, capacity-building, and long-term protection of vultures.
• यह समझौता गिद्धों के वैज्ञानिक प्रजनन, निगरानी, क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक संरक्षण पर केंद्रित है।
• The two critically endangered vulture species covered under the MoU are the Oriental White-backed Vulture and the Long-billed Vulture.
• इस समझौते के अंतर्गत शामिल दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियाँ हैं — ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड गिद्ध और लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध।

Ques: Cashless Treatment for Road Accident Victims Scheme, 2025 has been notified under which provision of the Motor Vehicles Act?
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अधिसूचित की गई है?

A) Section 146 of Motor Vehicles Act
B) Section 159 of Motor Vehicles Act
C) Section 162 of Motor Vehicles Act
D) Section 164 of Motor Vehicles Act
E) Section 166 of Motor Vehicles Act

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Cashless Treatment for Road Accident Victims Scheme, 2025 has been notified under Section 162 of the Motor Vehicles Act, 1988.
• सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
• The scheme provides cashless medical treatment up to ₹1.5 lakh per victim for a maximum period of 7 days from the date of accident.
• इस योजना के अंतर्गत प्रति पीड़ित अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक प्रदान किया जाएगा।
• All motor vehicle road accident victims are eligible under the scheme, irrespective of the type of road or vehicle involved.
• सड़क या वाहन की श्रेणी की परवाह किए बिना सभी मोटर वाहन सड़क दुर्घटना पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे।
• Stabilisation treatment is provided for up to 24 hours in non-life-threatening cases and up to 48 hours in life-threatening cases.
• गैर-जीवन-घातक मामलों में 24 घंटे तक और जीवन-घातक मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।
• The scheme is implemented through the integration of eDAR (electronic Detailed Accident Report) and TMS 2.0 platforms.
• यह योजना eDAR (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) और TMS 2.0 प्लेटफॉर्म के एकीकरण के माध्यम से लागू की जा रही है।

Ques: Which district became the first in India to implement online property tax collection through the SAMARTH Panchayat portal?
कौन-सा जिला SAMARTH पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह लागू करने वाला भारत का पहला जिला बना है?

A) Raipur, Chhattisgarh / रायपुर, छत्तीसगढ़
B) Durg, Chhattisgarh / दुर्ग, छत्तीसगढ़
C) Bilaspur, Chhattisgarh / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
D) Dhamtari, Chhattisgarh / धमतरी, छत्तीसगढ़
E) Bastar, Chhattisgarh / बस्तर, छत्तीसगढ़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Dhamtari district in Chhattisgarh has become the first district in India to implement online property tax collection through the SAMARTH Panchayat portal.
• छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला SAMARTH पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है।
• The initiative was launched on January 29, 2026, at Saankra (Sankara) Gram Panchayat in Nagri block.
• इस पहल की शुरुआत 29 जनवरी 2026 को नगरी ब्लॉक के सांकरा ग्राम पंचायत में की गई।
• The digital property tax collection system has been rolled out across nearly 400 gram panchayats in the district.
• यह डिजिटल संपत्ति कर संग्रह प्रणाली जिले की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है।

Recent News Headlines Related to First in india and world :

• India's first dedicated Glass Museum is being developed in Firozabad, Uttar Pradesh, popularly known as the "Glass City of India."
• भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बनाया जा रहा है, जिसे "भारत की कांच नगरी" कहा जाता है।

• Arjunbhai Modhwadia, Gujarat's Minister of Science and Technology, laid the foundation stone of India's first integrated private-sector satellite plant 'Palmnaro'.
• गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने भारत के पहले एकीकृत निजी क्षेत्र सैटेलाइट संयंत्र 'Palmnaro' की आधारशिला रखी।

• Lucknow became Uttar Pradesh's first 'Zero Fresh Waste Dump City' after achieving 100% scientific processing of municipal solid waste under the Swachh Bharat Mission-Urban.
• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत नगर ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल करने के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला 'जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी' बना।

• Prime Minister Narendra Modi flagged off India's first Vande Bharat Sleeper Train between Howrah and Guwahati (Kamakhya) from Malda Town Railway Station.
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हावड़ा–गुवाहाटी (कामाख्या) मार्ग पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

• Tamil Nadu has unveiled India's first Deep Tech Startup Policy 2025–26 to promote cutting-edge research and innovation. The policy earmarks an investment of ₹100 crore to support 100 deeptech start-ups across the state.
• तमिलनाडु ने अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है। इस नीति के तहत राज्य भर में 100 डीपटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।

• Indian Institute of Information Technology, Dharwad (IIIT-D) will deploy India's first commercial quantum computer at its Centre for Excellence in Quantum AI and Computing. The deployment will be carried out in collaboration with Bengaluru-based deeptech startup QpiAI.
• भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ (IIIT-D) अपने क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग उत्कृष्टता केंद्र में भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करेगा। यह स्थापना बेंगलुरु स्थित डीपटेक स्टार्टअप QpiAI के सहयोग से की जाएगी।

Ques: From which date will the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026 come into effect?
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?

A) 1 January 2026
B) 1 March 2026
C) 1 April 2026
D) 15 April 2026
E) 1 July 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has notified the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026, which will come into force from 1 April 2026.
• भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
• The rules have been issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).
• ये नियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी किए गए हैं।
• The SWM Rules, 2026 integrate the principles of Circular Economy and Extended Producer Responsibility (EPR).
• SWM नियम, 2026 में सर्कुलर इकोनॉमी और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।
• Four-stream segregation of solid waste at source has been made mandatory.
• स्रोत पर ठोस कचरे का चार-धारा पृथक्करण अनिवार्य किया गया है।
• Environmental compensation will be imposed based on the 'Polluter Pays' principle for non-compliance.
• अनुपालन न करने पर 'Polluter Pays' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा।
• Penalties include violations such as operating without registration, false reporting, and improper waste management practices.
• दंड में बिना पंजीकरण संचालन, गलत रिपोर्टिंग, और अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन जैसे उल्लंघन शामिल हैं।
• The rules introduce graded development criteria around solid waste processing and disposal facilities to enable faster land allocation.

Ques: In Agriculture Year 2024–25, which sector recorded higher production in India?
कृषि वर्ष 2024–25 में भारत में किस क्षेत्र का उत्पादन अधिक रहा?

A) Foodgrains / खाद्यान्न
B) Pulses / दलहन
C) Oilseeds / तिलहन
D) Horticulture / बागवानी
E) Cotton / कपास

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's foodgrain production in Agriculture Year (AY) 2024–25 is estimated at 357.7 million tonnes (MT).
• कृषि वर्ष 2024–25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 357.7 मिलियन टन (MT) रहने का अनुमान है।
• The increase in foodgrain output is attributed to a good monsoon and higher production of rice, wheat, maize, and coarse cereals.
• खाद्यान्न उत्पादन में यह वृद्धि अच्छे मानसून तथा चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाजों के अधिक उत्पादन के कारण हुई है।
• Horticulture production in 2024–25 reached 362.08 million tonnes (MT).
• 2024–25 में बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन (MT) तक पहुंच गया।
• Horticulture output surpassed foodgrain production, highlighting increasing diversification in Indian agriculture.
• बागवानी उत्पादन ने खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया, जो भारतीय कृषि में बढ़ते विविधीकरण को दर्शाता है।
• Horticulture contributes about 33% of agricultural Gross Value Added (GVA), emerging as a key driver of agricultural growth.
• बागवानी कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 33% का योगदान देती है और कृषि विकास का प्रमुख चालक बनकर उभरी है।

Ques: Which organisation launched the ACASA-India digital platform while reviewing 15 years of the NICRA programme?
किस संगठन ने NICRA कार्यक्रम के 15 वर्ष पूरे होने पर ACASA-India डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया?

A) Indian Council of Agricultural Research (ICAR) / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
B) NITI Aayog / नीति आयोग
C) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
D) Food and Agriculture Organization (FAO) / खाद्य एवं कृषि संगठन
E) Indian Meteorological Department (IMD) / भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) reviewed the progress of the National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) programme, which has completed 15 years, and launched the ACASA-India digital platform.
• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने राष्ट्रीय जलवायु-सहिष्णु कृषि नवाचार (NICRA) कार्यक्रम के 15 वर्ष पूरे होने पर उसकी प्रगति की समीक्षा की और ACASA-India डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
• The review was conducted during a workshop organised by ICAR and the Borlaug Institute for South Asia (BISA).
• यह समीक्षा ICAR और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (BISA) द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान की गई।
• M L Jat, Director General (DG), ICAR and Secretary, Department of Agricultural Research and Education (DARE), was a key figure in the initiative.
• एम. एल. जाट, ICAR के महानिदेशक (DG) एवं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव, इस पहल से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रहे।
• The programme covers 200+ locations across 151 climate-vulnerable districts.
• यह कार्यक्रम 151 जलवायु-संवेदनशील जिलों में 200 से अधिक स्थानों को कवर करता है।
• Its objective is to enhance the climate resilience of Indian agriculture, with a focus on droughts, floods, heat stress, cyclones, and rainfed farming systems.
• इसका उद्देश्य भारतीय कृषि की जलवायु सहनशीलता बढ़ाना है, विशेष रूप से सूखा, बाढ़, हीट स्ट्रेस, चक्रवात और वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना।
• NICRA stands for National Innovations in Climate Resilient Agriculture.

Ques: Which state presented India's first elderly budget linking local body funds to the senior citizen population?

किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों की आबादी से स्थानीय निकाय फंड को जोड़ते हुए भारत का पहला बुजुर्ग बजट प्रस्तुत किया?

A) Tamil Nadu / तमिलनाडु
B) Kerala / केरल
C) Maharashtra / महाराष्ट्र
D) Karnataka / कर्नाटक
E) Odisha / ओडिशा

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Kerala has presented India's first-ever budget exclusively focused on senior citizens.
• केरल ने वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित भारत का पहला विशेष बुजुर्ग बजट प्रस्तुत किया है।
• The budget proposes linking the devolution of funds to local bodies with the proportion of senior citizens in the population.
• इस बजट में स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले फंड को वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।
• The initiative aims to strengthen welfare services such as healthcare, social security, and elderly care infrastructure at the grassroots level.
• इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्ग देखभाल अवसंरचना को मजबूत करना है।
• Kerala has one of the highest proportions of elderly population in India, making age-responsive budgeting especially important.
• केरल में भारत में बुजुर्ग आबादी का अनुपात सबसे अधिक है, जिससे आयु-संवेदनशील बजटिंग अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
• The initiative aligns with Kerala's broader focus on inclusive governance and effective management of demographic transition.
• यह पहल समावेशी शासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रभावी प्रबंधन पर केरल के व्यापक फोकस के अनुरूप है।

Ques: Where is the Beating Retreat ceremony usually held in India?
भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह सामान्यतः कहाँ आयोजित किया जाता है?

A) Vijay Chowk, New Delhi / विजय चौक, नई दिल्ली
B) Rajpath, New Delhi / राजपथ, नई दिल्ली
C) Red Fort, New Delhi / लाल किला, नई दिल्ली
D) India Gate, New Delhi / इंडिया गेट, नई दिल्ली
E) Rashtrapati Bhavan, New Delhi / राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi attended the Beating Retreat ceremony, marking the formal conclusion of India's Republic Day celebrations.
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लिया, जो गणतंत्र दिवस समारोहों के औपचारिक समापन का प्रतीक है।
• The ceremony features synchronised musical performances by bands of the Indian Army, Navy and Air Force.
• इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंडों द्वारा समन्वित संगीत प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।
• In India, the Beating Retreat ceremony is organised three days after Republic Day, i.e., on 29 January.
• भारत में यह समारोह गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद, अर्थात 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
• The event is traditionally held at Vijay Chowk, New Delhi.
• यह कार्यक्रम परंपरागत रूप से नई दिल्ली के विजय चौक में आयोजित किया जाता है

Ques: Which day is observed on 27 January to commemorate the victims of the Holocaust?
27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति में कौन-सा दिवस मनाया जाता है?

A) International Holocaust Remembrance Day / अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस
B) World Peace Day / विश्व शांति दिवस
C) International Human Rights Day / अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
D) International Justice Day / अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस
E) World Refugee Day / विश्व शरणार्थी दिवस

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• 27 January is observed as the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust, also known as International Holocaust Remembrance Day.
• 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है।
• The observance was started in 2006 following a resolution of the United Nations General Assembly.
• इस दिवस की शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद की गई थी।
• The theme for 2026 is “Holocaust Remembrance for Dignity and Human Rights.”
• 2026 की थीम है — “गरिमा और मानवाधिकारों के लिए होलोकॉस्ट स्मरण”।
• The day aims to honour the memory of millions of victims of the Holocaust and promote human dignity, tolerance, and human rights.
• इस दिवस का उद्देश्य होलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों की स्मृति को सम्मान देना और मानव गरिमा, सहिष्णुता एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।

Important days :

- 1 January : Global Family Day (Started in 2000)
- 2 January : World Introvert Day (Theme 2026 Quietly Changing Tomorrow)
- 3 January : International Mind-Body Wellness Day
- 4 January : World Braille Day (Started in 2018)
- 5 January : National Bird Day (started in 2002)
- 6 January : World Day of War Orphans (Started in 1995)
- 6 January : 9th National Siddha Day ("Siddha for Global Health.")
- 8 January : Earth's Rotation Day
- 9 January : Pravasi Bharatiya Divas (PBD)
- 10 January : World Hindi Day, also known as Vishwa Hindi Diwas
- 12 January : National Youth Day, also known as Rashtriya Yuva Divas and Vivekananda Jayanti
- 15 January : Indian Army Day (theme 2026 "Year of Networking and Data Centricity.")
- 16 January : Foundation Day of Lokpal of India
- 16 January : National Startup Day (Started in 2016)
- 19 January : 21st National Disaster Response Force (NDRF) Raising Day
- 20 January : Penguin Awareness Day (Started in 1972)
- 23 January : Parakram Diwas (Marks the 129th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose)
- 24 January : International Day of Education (Theme 2026 The power of youth in co-creating education)
- 24 January : 19th National Girl Child Day (NGCD) (Started in 2008 by the Ministry of Women and Child Development (MoWCD))
- 25 January : National Tourism Day (Started in 1982)
- 25 January : National Voters' Day (Theme : "My India, My Vote")
- 26 January : International Customs Day (ICD) (Theme 2026 : Customs protecting society through vigilance and commitment)
- 26 January : 3rd International Day of Clean Energy (Theme : "Clean Energy for People and Planet.")
- 27 to 30 January 2026 : 4th edition of India Energy Week (IEW) 2026
- 27 January : National Geographic Day